Shree Krishna International Journal of Multidisciplinary Studies
ISSN: xxxx-xxxx (Online)

स्वरोजगार योजनाएँ एवं ग्रामीण आर्थिक विकास: संभावनाएँ, चुनौतियाँ एवं समाधान

राजकुमार साहू, संशोधक विदयार्थी, अर्थाशास्त्र विभाग
डॉ० संजीव कुमार (एसोसिएट प्रोफेसर), अर्थशास्त्र विभाग
मेजर एस०डी० सिंह विश्वविद्यालय, फर्रूखाबाद

शोध सार

यह शोध-पत्र "स्वरोजगार योजनाएँ एवं ग्रामीण आर्थिक विकास" विषय पर आधारित है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं की भूमिका एवं उनके प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जहाँ बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा तथा सीमित आर्थिक संसाधन जैसी समस्याएँ विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। इन चुनौतियों के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा अनेक स्वरोजगार योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य ग्रामीण जनता को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। प्रस्तुत अध्ययन में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) जैसी योजनाओं का अध्ययन किया गया है। यह शोध मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है, जिनमें पुस्तकें, शोध-पत्र, सरकारी रिपोर्ट एवं इंटरनेट स्रोत शामिल हैं। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि स्वरोजगार योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण, कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास तथा गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता की भावना विकसित हुई है तथा पलायन की समस्या में भी कमी आई है। हालांकि जागरूकता की कमी, तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव तथा ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयाँ अभी भी प्रमुख चुनौतियाँ हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि स्वरोजगार योजनाएँ ग्रामीण आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

कुंजी शब्द

स्वरोजगार योजनाएँ, ग्रामीण आर्थिक विकास, ग्रामीण बेरोजगारी, महिला सशक्तिकरण, उद्यमिता विकास, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुद्रा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, कौशल विकास, आत्मनिर्भर भारत, कुटीर उद्योग, ग्रामीण उत्थान।

राजकुमार साहू
rajkumarsahoo20@gmail.com

डॉ० संजीव कुमार
dr.skj2008@gmail.com

Paper Received: 22/05/2026
Paper Revised: --------------
Paper Accepted: 28/05/2026

१. प्रस्तावना

भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा इसकी अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग तथा लघु व्यवसायों पर आधारित है। देश की आर्थिक प्रगति में ग्रामीण क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु आज भी ग्रामीण भारत अनेक आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से जूझ रहा है। सीमित संसाधन, अशिक्षा, तकनीकी ज्ञान का अभाव तथा रोजगार के सीमित अवसर ग्रामीण विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं (देशपांडे, खन्ना, एवं वालिया, २०२४)। ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण आर्थिक गतिविधियों का अपेक्षित विकास नहीं हो पाता, जिससे ग्रामीण जनता का जीवन स्तर प्रभावित होता है।

ग्रामीण भारत में बेरोजगारी एवं गरीबी एक गंभीर समस्या के रूप में विद्यमान हैं। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता तथा कृषि भूमि का निरंतर विभाजन रोजगार के अवसरों को सीमित कर देता है। इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में ग्रामीण युवा बेरोजगार रहते हैं अथवा अल्प रोजगार की स्थिति का सामना करते हैं। बेरोजगारी के कारण ग्रामीण परिवारों की आय कम रहती है, जिससे गरीबी, कुपोषण तथा सामाजिक असमानता जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। रोजगार के अभाव में ग्रामीण लोग बेहतर अवसरों की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने के लिए विवश हो जाते हैं (चो, रोबालिनो, एवं वॉटसन, २०१६)।

ऐसी परिस्थितियों में स्वरोजगार की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। स्वरोजगार का अर्थ है — व्यक्ति द्वारा स्वयं के कौशल, संसाधनों तथा प्रयासों के आधार पर रोजगार प्राप्त करना। स्वरोजगार व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है तथा उसे आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी, पशुपालन, हस्तशिल्प, मधुमक्खी पालन, सिलाई-कढ़ाई, खाद्य प्रसंस्करण तथा छोटे उद्योग स्वरोजगार के प्रमुख माध्यम हैं। स्वरोजगार न केवल व्यक्ति की आय में वृद्धि करता है, बल्कि समाज में उद्यमिता एवं आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देता है (तमवाडा, श्रीवास्तव, एवं मिश्रा, २०२२)।

ग्रामीण विकास में स्वरोजगार का विशेष महत्व है। यह रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन तथा महिला सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम है। स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण युवाओं एवं महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है। इससे स्थानीय संसाधनों का उचित उपयोग संभव होता है तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। इसके अतिरिक्त स्वरोजगार ग्रामीण पलायन को कम करने तथा आत्मनिर्भर ग्रामीण समाज के निर्माण में भी सहायक सिद्ध होता है (कुमार एवं कुमरा, २०२१)।

ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा विभिन्न स्वरोजगार योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण जनता को रोजगार, प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का प्रयास किया जा रहा है (कुमार एवं शोभना, २०२३; गुरिया, २०२४)।

२. साहित्य समीक्षा

साहित्य समीक्षा किसी भी शोध कार्य का एक महत्वपूर्ण भाग होती है, क्योंकि इसके माध्यम से शोध विषय से संबंधित पूर्व अध्ययनों, विचारों तथा निष्कर्षों का विश्लेषण किया जाता है। प्रस्तुत शोध "स्वरोजगार योजनाएँ एवं ग्रामीण आर्थिक विकास" विषय पर आधारित है। इस विषय के अध्ययन हेतु विभिन्न शोध-पत्रों, लेखों तथा अकादमिक स्रोतों का अध्ययन किया गया है।

कुमार एवं कुमरा (२०२१) ने भारत के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों का व्यवस्थित अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण संस्थान ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास, आत्मविश्वास तथा उद्यमिता की भावना विकसित

करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अध्ययन के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों में स्वरोजगार अपनाने की प्रवृत्ति अधिक देखी गई।

कुमार एवं शोभना (२०२३) ने पूर्वोत्तर भारत में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की उपलब्धियों एवं प्रभाव का मूल्यांकन किया। उनके अनुसार यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, सूक्ष्म उद्योगों के विकास तथा आर्थिक उन्नति को प्रोत्साहित करने में प्रभावी सिद्ध हुई है।

कुमार एवं ओजुकुम (२०२२) ने नागालैंड के कोहिमा जिले में जनजातीय लाभार्थियों पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के प्रभाव का अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि इस योजना ने जनजातीय समुदायों में उद्यमिता विकास, आय वृद्धि तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है।

मिश्रा एवं पांडेय (२०२१) ने बिलासपुर जिले में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की वृद्धि पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के प्रभाव का विश्लेषण किया। शोध के अनुसार इस योजना ने नए उद्योगों की स्थापना, स्थानीय रोजगार सृजन तथा आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

गुरिया (२०२४) ने भारत में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं प्रभाव का अध्ययन किया। अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ कि योजना ने स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि की है, किन्तु इसके प्रभावी संचालन हेतु प्रशासनिक दक्षता, जागरूकता तथा ऋण वितरण प्रक्रिया में सुधार आवश्यक है।

मीना एवं कुमारी (२०२५) ने ग्रामीण राजस्थान में सरकारी रोजगार योजनाओं एवं सतत उद्यमिता विकास का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रेरित करने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सहायक है।

तमवाडा, श्रीवास्तव एवं मिश्रा (२०२२) ने शिक्षा, सामाजिक पहचान एवं स्वरोजगार के मध्य संबंध का अध्ययन किया। उनके अनुसार शिक्षा एवं सामाजिक परिस्थितियाँ स्वरोजगार के अवसरों को प्रभावित करती हैं तथा आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

देशपांडे, खन्ना एवं वालिया (२०२४) ने भारत के बड़े आजीविका कार्यक्रमों के श्रम बाजार पर प्रभाव का अध्ययन किया। शोध में यह पाया गया कि सरकारी आजीविका योजनाओं ने ग्रामीण रोजगार, आय वृद्धि तथा आर्थिक स्थिरता को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

चो, रोबालिनो एवं वॉटसन (२०१६) ने कमजोर वर्गों के लिए स्वरोजगार एवं लघु उद्यमिता को समर्थन देने वाले कार्यक्रमों का अध्ययन किया। उनके अनुसार प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता तथा नीतिगत सहयोग के माध्यम से स्वरोजगार योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

भास्करण (२०११) ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के प्रदर्शन का अध्ययन करते हुए बताया कि यह योजना ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार सृजन तथा उद्यमिता विकास में सहायक सिद्ध हुई है।

उपरोक्त अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि स्वरोजगार योजनाएँ ग्रामीण आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में क्रियान्वयन के लिए जागरूकता, कौशल विकास, वित्तीय सहायता तथा सरल ऋण सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि

३.शोध पद्धति

(क) शोध का प्रकार

वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध

(ख) डेटा का स्रोत

द्वितीयक आँकड़े (Secondary Data)

(ग) डेटा संग्रह के स्रोत

पुस्तकें

शोध-पत्र एवं जर्नल

सरकारी रिपोर्ट

इंटरनेट स्रोत

समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ

(घ) अध्ययन का उद्देश्य

स्वरोजगार योजनाओं एवं ग्रामीण आर्थिक विकास के संबंध का अध्ययन करना।

योजनाओं के प्रभाव एवं चुनौतियों का विश्लेषण करना।

४.स्वरोजगार की अवधारणा

४.१ स्वरोजगार का अर्थ एवं परिभाषा

स्वरोजगार का अर्थ है स्वयं के कौशल, ज्ञान, अनुभव एवं संसाधनों के आधार पर रोजगार प्राप्त करना। इसमें व्यक्ति किसी सरकारी या निजी नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं का व्यवसाय, उद्योग अथवा सेवा कार्य प्रारंभ करता है। स्वरोजगार व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करता है तथा आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है। वर्तमान समय में यह रोजगार का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ रोजगार के अवसर सीमित होते हैं। स्वरोजगार केवल आय अर्जित करने का साधन नहीं है, बल्कि यह उद्यमिता, आत्मविश्वास तथा सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देता है।

४.२ स्वरोजगार के प्रकार

स्वरोजगार के अनेक प्रकार हैं, जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी योग्यता एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्य कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित स्वरोजगार जैसे डेयरी उद्योग, पशुपालन, मधुमक्खी पालन एवं मत्स्य पालन अधिक प्रचलित हैं। इसके अतिरिक्त कुटीर एवं लघु उद्योग जैसे हस्तशिल्प, हथकरघा, अगरबत्ती एवं मोमबत्ती निर्माण भी स्वरोजगार के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। सेवा आधारित कार्यों में सिलाई-कढ़ाई, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर तथा कंप्यूटर सेवाएँ शामिल हैं। वर्तमान समय में डिजिटल तकनीक के विकास के कारण ई-कॉमर्स, ऑनलाइन सेवाएँ तथा फ्रीलांसिंग जैसे आधुनिक स्वरोजगार के अवसर भी तेजी से बढ़ रहे हैं।

४.३ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार की आवश्यकता

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी, गरीबी तथा सीमित रोजगार अवसरों के कारण स्वरोजगार की आवश्यकता अत्यधिक बढ़ गई है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता एवं कृषि भूमि के विभाजन के कारण सभी लोगों को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में स्वरोजगार आय का वैकल्पिक स्रोत प्रदान करता है तथा ग्रामीण जनता को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है। स्वरोजगार के माध्यम से ग्रामीण युवाओं एवं महिलाओं को रोजगार प्राप्त होता है, जिससे उनकी आय एवं जीवन स्तर में सुधार आता है। यह ग्रामीण पलायन को रोकने, स्थानीय संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देने तथा कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास में भी सहायक सिद्ध होता है। इस प्रकार स्वरोजगार ग्रामीण आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भर ग्रामीण समाज के निर्माण का एक महत्वपूर्ण साधन है।

SIJMS.COM

५. प्रमुख स्वरोजगार योजनाएँ

५.१ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) भारत सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण स्वरोजगार योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करना तथा सूक्ष्म एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए बैंक ऋण एवं सब्सिडी प्रदान की जाती है। PMEGP की प्रमुख विशेषता यह है कि यह स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करती है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देती है। इस योजना से रोजगार सृजन, ग्रामीण उद्योगों का विकास तथा आर्थिक सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुए हैं।

५.३ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) छोटे व्यापारियों, उद्यमियों एवं स्वरोजगार से जुड़े व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत बिना गारंटी ऋण प्रदान किया जाता है। ऋण को तीन श्रेणियों — शिशु, किशोर एवं तरुण — में विभाजित किया गया है। शिशु श्रेणी में ₹50,000 तक, किशोर श्रेणी में ₹5 लाख तक तथा तरुण श्रेणी में ₹10 लाख तक ऋण दिया जाता है। इस योजना ने छोटे व्यवसायों, स्वरोजगार एवं ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा बेरोजगार युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान किया है।

५.४ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) ग्रामीण गरीब परिवारों के आर्थिक विकास एवं महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का गठन किया जाता है, जिसके माध्यम से महिलाओं को बचत, ऋण सुविधा एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। NRLM ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा उनकी सामाजिक स्थिति को सशक्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों एवं सामूहिक उद्यमों को भी बढ़ावा मिला है।

५.५ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) का उद्देश्य युवाओं को विभिन्न तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशलों का प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सकें या स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर सकें। इस योजना के अंतर्गत कंप्यूटर शिक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, सिलाई-कढ़ाई, इलेक्ट्रिशियन कार्य एवं अन्य तकनीकी प्रशिक्षण दिए जाते हैं। PMKVY ने युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन एवं स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि की है। यह योजना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जाती है।

५.६ स्टार्टअप इंडिया योजना

स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य देश में नवाचार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को नए व्यवसाय एवं स्टार्टअप स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण एवं विभिन्न सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण एवं डिजिटल सेवाओं से संबंधित स्टार्टअप तेजी से विकसित हो रहे हैं। यह योजना ग्रामीण युवाओं में नवाचार की भावना विकसित करने तथा स्वरोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ग्रामीण आर्थिक विकास में।

६.स्वरोजगार योजनाओं की भूमिका

स्वरोजगार योजनाएँ ग्रामीण आर्थिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सीमित अवसरों के कारण बेरोजगारी एवं गरीबी की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। ऐसी स्थिति में स्वरोजगार

योजनाएँ रोजगार सृजन का प्रभावी माध्यम बनकर उभरी हैं। इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं।स्वरोजगार योजनाएँ गरीबी उन्मूलन में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। जब ग्रामीण लोगों को स्थायी आय का स्रोत प्राप्त होता है, तो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है तथा जीवन स्तर बेहतर बनता है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों (SHGs) एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं ने आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। महिलाओं की आय में वृद्धि होने से परिवार एवं समाज दोनों के विकास में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है।

इन योजनाओं ने ग्रामीण उद्योगों एवं कुटीर उद्योगों के विकास को भी बढ़ावा दिया है। हस्तशिल्प, डेयरी, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण एवं अन्य लघु उद्योगों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ी हैं। इसके अतिरिक्त स्वरोजगार योजनाओं के कारण ग्रामीण लोगों का शहरों की ओर पलायन भी कम हुआ है, क्योंकि अब उन्हें अपने ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। स्वरोजगार योजनाएँ स्थानीय संसाधनों के उचित उपयोग को भी प्रोत्साहित करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का उपयोग करके छोटे उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। इससे आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के निर्माण को बल मिला है तथा ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को गति प्राप्त हुई है।

६.परिणाम एवं विश्लेषण

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि स्वरोजगार योजनाओं ने ग्रामीण आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) तथा कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण युवाओं एवं महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। इन योजनाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों एवं स्वरोजगार आधारित गतिविधियों में वृद्धि हुई है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला है।

स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है तथा उनमें आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास का विकास हुआ है। कई अध्ययनों में यह पाया गया कि स्वरोजगार योजनाओं ने ग्रामीण बेरोजगारी एवं गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त युवाओं में उद्यमिता की भावना विकसित हुई है तथा स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हुआ है। स्वरोजगार योजनाओं के कारण कई ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की ओर पलायन की समस्या में भी कमी देखने को मिली है।

हालाँकि योजनाओं के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, फिर भी कई समस्याएँ इनके प्रभाव को सीमित करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी, तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव, बैंक ऋण प्राप्त करने में कठिनाई तथा विपणन सुविधाओं की कमी प्रमुख चुनौतियाँ हैं। प्रशासनिक जटिलताएँ एवं डिजिटल सुविधाओं की सीमित उपलब्धता भी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करती हैं। इसलिए योजनाओं के सफल संचालन हेतु प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, डिजिटल सुविधाओं एवं बाजार व्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक है।

स्वरोजगारो योजनाएँएँवंग्रामीण आर्थिक विकास

क्रमांक	प्रमुख परिणाम	विवरण
१	रोजगार सृजन	ग्रामीण युवाओं एवंमहिलाओं को रोजगार प्राप्त हुआ
२	महिला सशक्तिकरण	स्वयं सहायता समूहों के माध्यम सेमहिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई
३	ग्रामीण उद्योगों का विकास	कुटीर एवंसूक्ष्म उद्योगों मेंवृद्धि हुई
४	उद्यमिता विकास	युवाओं में स्वरोजगार एवं उद्यमिता की भावना विकसित हुई

५	ऋण सुविधा का प्रभाव	बैंकिंग एवं ऋण सुविधाओं से स्वरोजगार को बढ़ावा मिला
६	स्थानीय संसाधनों का उपयोग	स्थानीय उत्पादों एवं उद्योगों को प्रोत्साहन मिला
७	गरीबी एवं पलायन में कमी	ग्रामीण आय मेंवृद्धि एवं पलायन में कमी देखी गई

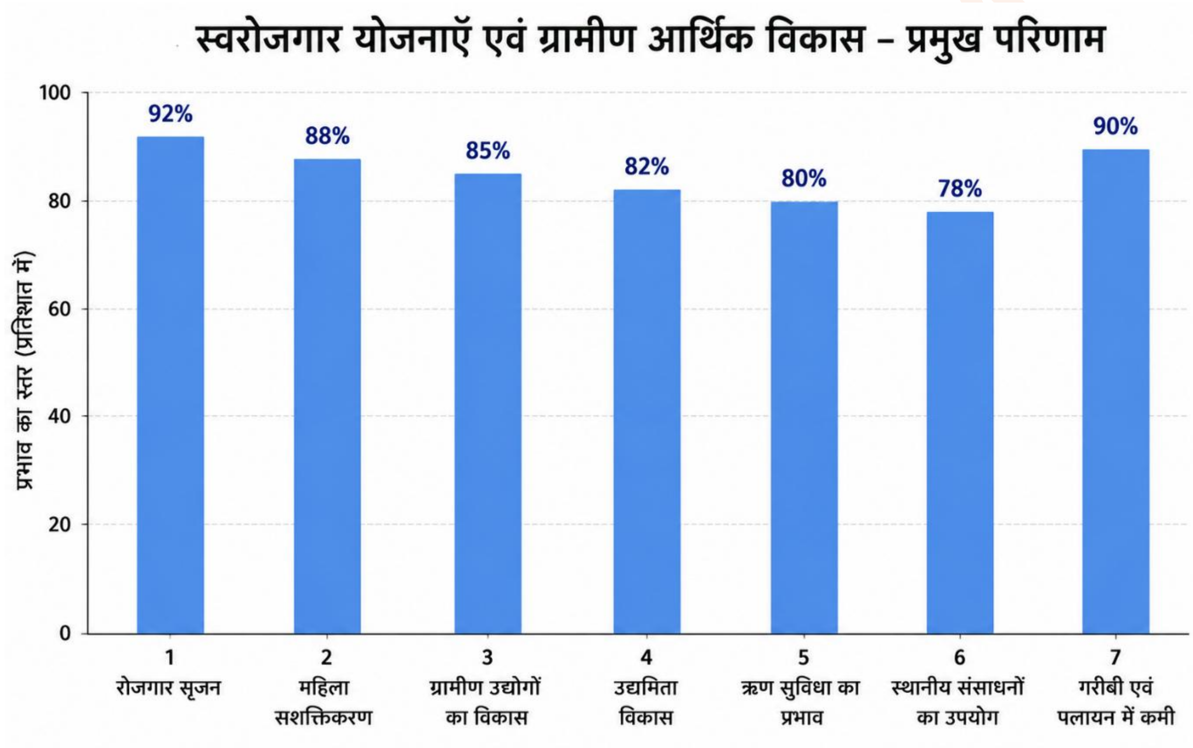

चित्र –स्वरोजगार योजनाओं का प्रभाव

विश्लेषणात्मक निष्कर्ष

अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि स्वरोजगार योजनाएँ ग्रामीण आर्थिक विकास के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई हैं। इन योजनाओं ने रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण तथा ग्रामीण उद्योगों के विकास में सकारात्मक योगदान दिया है। हालांकि जागरूकता की कमी, प्रशिक्षण का अभाव एवं ऋण संबंधी समस्याएँ अभी भी प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं। अतः योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण, डिजिटल सुविधा एवं सरल वित्तीय सहायता व्यवस्था को सुदृढ़ करना आवश्यक है।

७. स्वरोजगार योजनाओं के समक्ष चुनौतियाँ

प्रस्तुत अध्ययन के परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि स्वरोजगार योजनाओं ने ग्रामीण आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान दिया है, किंतु इनके प्रभावी क्रियान्वयन में अनेक चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के प्रति पर्याप्त जागरूकता का अभाव है, जिसके

कारण कई पात्र व्यक्ति योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। विशेष रूप से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को योजनाओं की जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती। अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक कौशल की कमी स्वरोजगार योजनाओं की सफलता में बाधा उत्पन्न करती है। कई लाभार्थियों को व्यवसाय प्रबंधन, विपणन एवं आधुनिक तकनीकों का पर्याप्त ज्ञान नहीं होता, जिसके कारण वे अपने उद्योगों को स्थायी रूप से विकसित नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त बैंक ऋण प्राप्त करने की जटिल प्रक्रिया, दस्तावेजों की कमी तथा गारंटी संबंधी समस्याओं के कारण ग्रामीण लोगों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण उत्पादों के लिए उचित बाजार एवं विपणन सुविधाओं का अभाव भी एक प्रमुख समस्या है। कई बार उत्पाद तैयार होने के बाद भी उन्हें उचित मूल्य एवं बाजार नहीं मिल पाता। अध्ययन में यह भी पाया गया कि भ्रष्टाचार, प्रशासनिक जटिलताएँ तथा डिजिटल सुविधाओं की कमी योजनाओं के प्रभाव को सीमित करती हैं। इसलिए इन चुनौतियों का समाधान करना ग्रामीण स्वरोजगार योजनाओं की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है।

८. सुधारात्मक सुझाव

अध्ययन के परिणामों के आधार पर यह आवश्यक प्रतीत होता है कि स्वरोजगार योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ठोस सुधारात्मक कदम उठाए जाएँ। सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु विशेष अभियान चलाए जाने चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही ग्रामीण युवाओं एवं महिलाओं के लिए तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे वे आधुनिक कौशल प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सकें।

अध्ययन में बैंक ऋण संबंधी समस्याएँ प्रमुख रूप से सामने आई हैं, इसलिए ऋण प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाया जाना आवश्यक है। लाभार्थियों को कम ब्याज दर पर आसान ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ग्रामीण उत्पादों के विपणन के लिए डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हो सके।

महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता योजनाएँ संचालित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। यदि इन सुझावों को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, तो स्वरोजगार योजनाएँ ग्रामीण विकास में और अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो सकती हैं।

९. निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि स्वरोजगार योजनाएँ ग्रामीण आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इन योजनाओं ने ग्रामीण युवाओं एवं महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने, गरीबी कम करने तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), मुद्रा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) तथा कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों एवं उद्यमिता का विकास हुआ है।

अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि स्वरोजगार योजनाओं के कारण महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार आया है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हुआ है। कई क्षेत्रों में पलायन की समस्या में भी कमी देखने को मिली है। हालांकि जागरूकता की कमी, तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव, ऋण संबंधी कठिनाइयाँ एवं विपणन समस्याएँ अभी भी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करती हैं। अतः यह आवश्यक है कि सरकार, वित्तीय संस्थाएँ एवं समाज मिलकर योजनाओं के प्रभावी संचालन हेतु कार्य करें। यदि उचित प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, डिजिटल सुविधाएँ एवं बाजार व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, तो स्वरोजगार योजनाएँ ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर, समृद्ध एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती हैं।

संदर्भ सूची

१. कुमार, पवन, एवं कुमरा, रितु। (२०२१)। भारत में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों का एक व्यवस्थित अध्ययन। प्रबंधन: इंडियन जर्नल ऑफ मैनेजमेंट, १४(१०), ३८–४९।

२. कुमार, जे. सुरेश, एवं शोभना, डी। (२०२३)। पूर्वोत्तर भारत में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के प्रदर्शन एवं उपलब्धियों का व्यापक मूल्यांकन। ईपीआरए इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज़, १०(९)।

३. कुमार, जे. सुरेश, एवं ओजुकुम, इम्नाओनेन। (२०२२)। नागालैंड के कोहिमा जिले में जनजातीय लाभार्थियों के उद्यमिता विकास पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का प्रभाव। इंटरनेशनल जर्नल फॉर रिसर्च ट्रेंड्स एंड इनोवेशन, ७(६), २१६४–२१६७।

४. मिश्रा, प्रियांक, एवं पांडेय, सरिता। (२०२१)। बिलासपुर जिले में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की वृद्धि पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स।

५. गुरिया, अमर कुलदीप। (२०२४)। भारत में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं प्रभाव का अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ऑल रिसर्च एजुकेशन एंड साइंटिफिक मेथड्स।

६. मीना, आरती, एवं कुमारी, पिंकी। (२०२५)। ग्रामीण राजस्थान में सरकारी रोजगार कार्यक्रम एवं सतत उद्यमिता विकास: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का एक अध्ययन। ईपीआरए इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज़, १२(१२)।

७. तमवाडा, जगन्नाध पवन, श्रीवास्तव, मिली, एवं मिश्रा, तपस कुमार। (२०२२)। शिक्षा, सामाजिक पहचान एवं समय के साथ स्वरोजगार: एक विकासशील देश से प्रमाण। स्मॉल बिजनेस इकोनॉमिक्स, ५९, १४४९–१४६८।

८. देशपांडे, अश्विनी, खन्ना, शांतनु, एवं वालिया, दक्ष। (२०२४)। एक भारतीय पहेली? विश्व के सबसे बड़े आजीविका कार्यक्रम के श्रम बाजार पर प्रभाव। जर्नल ऑफ पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स, ३७, ६४।

९. चो, यूनयंग, रोबालिनो, डेविड, एवं वॉटसन, सामंथा। (२०१६)। स्वरोजगार एवं लघु उद्यमिता को समर्थन: कमजोर श्रमिकों की आजीविका सुधार हेतु संभावित कार्यक्रम। आईज़ेडए जर्नल ऑफ लेबर पॉलिसी, ५(७)।

१०. भास्करण, ई। (२०११)। भारत में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का प्रदर्शन। रिसर्चगेट प्रकाशन।